IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, December 2025
Impact Factor: 7.67

क्रिप्टोकरंसी और भारतीय वित्तीय प्रणाली: एक समीक्षा

डॉ. नम्रता दुबे

अतिथि विद्वान वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश

क्रिप्टोकरंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति (वर्चुअल डिजिटल एसेट - VDA) है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। भारत में यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन भारतीय वित्तीय प्रणाली पर इसका प्रभाव मिश्रित है। 2018 में आरबीआई के प्रतिबंध, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2023 में पीएमएलए के तहत FIU-IND पंजीकरण के बाद विनियमन की दिशा स्पष्ट हुई है। 2025 तक 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस बरकरार है, जबकि बजट 2025 में रिपोर्टिंग अनुपालन के लिए नए दंड (धारा 285BAA) लागू हुए हैं। आरबीआई ई-रुपया (सीबीडीसी) पायलट को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 19 बैंक शामिल हैं और ऑफलाइन भुगतान तथा प्रोग्रामेबिलिटी जैसी सुविधाएं हैं।

सकारात्मक प्रभावों में वित्तीय समावेशन, कम लेन-देन लागत, विदेशी निवेश और फिनटेक नवाचार शामिल हैं। नकारात्मक प्रभावों में अस्थिरता, मनी लॉन्डरिंग, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण की हानि और साइबर जोखिम हैं। इस समीक्षा में द्वितीयक स्रोतों (आरबीआई रिपोर्ट, सरकारी अधिसूचनाएं, शैक्षणिक पत्र और समाचार) के आधार पर विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष यह है कि संतुलित विनियमन और ई-रुपया को प्राथमिकता देकर क्रिप्टोकरंसी के लाभों को सुरक्षित तरीके से अपनाया जा सकता है।